

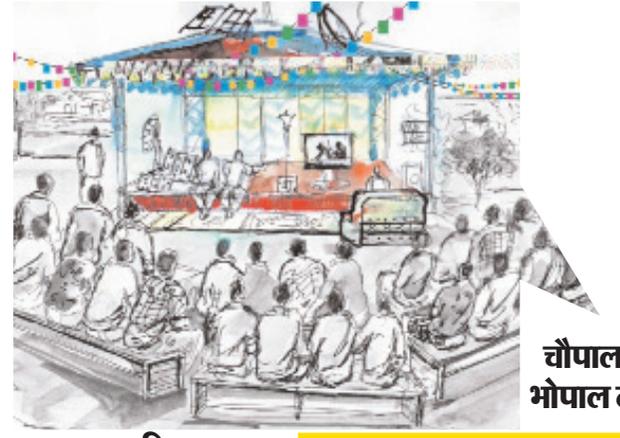
जागत



पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

# भाषा

हमारा

चौपाल से  
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 14 जून 2021, वर्ष-7, अंक-11

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुँना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

- उड़द की एमएसपी 6,000 से बढ़ाकर रुपए 6,300 की गई
- मूंगफली की एमएसपी 5275 से बढ़ाकर 5,550 रुपए की गई
- सूरजमुखी के बीज 5,885 से बढ़ाकर 6,015 रुपए की गई
- सोयाबीन की एमएसपी 3,880 से बढ़ाकर 3,950 रुपए की गई
- तिल की एमएसपी 6,855 से बढ़ाकर 7,307 रुपए की गई

## देश के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दिया बड़ा तोहफा

# खरीफ फसलों का 62 फीसदी बढ़ाया समर्थन मूल्य

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दी गई। तिल की एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान (सामान्य) की एमएसपी पिछले साल के 1,868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल की गई है यानी 72 रुपए ज्यादा। नई एमएसपी पर केंद्र के 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 1 जून को 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। 2020-21 में धान की एमएसपी को 1815 से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था।



### खरीफ की मुख्य फसलें

धान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। सितंबर-अक्टूबर में इनकी कटाई होती है।

### बाजरा में मिल रहा

### सबसे ज्यादा फायदा

बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार द्वारा जारी डाटा के अनुसार अगर लागत के मुकाबले रिटर्न की बात करें तो बाजरा इसमें सबसे आगे है। बाजरा का लागत के मुकाबले रिटर्न 85 फीसदी है। इसके बाद उड़द का नंबर आता है इसका रिटर्न 65 प्रतिशत रहा।



मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। विगत सात सालों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह वृद्धि होती रहेगी।



नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसान हित में कदम उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपने पसीने की सही कीमत मिलेगी। दलहन एवं तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा। वर्तमान में हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। केन्द्र द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 62 प्रतिशत तक की की गई वृद्धि सराहनीय है।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मप्र

# खतरे में सोयाबीन राज्य का दर्जा

## » खरीफ की बोवनी से पहले माफिया-कालाबाजारी सक्रिय

## » मप्र में खपाया जाएगा 900 करोड़ का नकली खाद-बीज

## » भनक लगते ही शिवराज सरकार ने भी बैठा दिया पहरा

अरविंद मिश्र, भोपाल

सोया स्टेट मप्र में पिछले चार साल से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। इस कारण किसान अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए कंपनियां, माफिया, कालाबाजारी संगठित होकर नकली बीज के साथ ही नकली खाद किसानों को बेच रहे हैं। किसानों को अधिक उत्पादन का प्रलोभन देकर प्रदेश में करीब 900 करोड़ रुपए के अमानक बीज और खाद खपाया जाएगा। हालांकि सरकार को इसकी भनक लग गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नकली बीजों से नुकसान पहुंचा है। कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में सोयाबीन का नकली बीज खपाए जाने से साल दर साल उत्पादन गिरता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से नकली खाद-बीज और मौसम की मार का असर जिस तरह पीले सोने पर पड़ा है, उससे मप्र का सोयाबीन राज्य का दर्जा खतरे में है। इसकी वजह है किसानों का सोयाबीन की खेती से मोहभंग होना। दरअसल, मौसम की बेरुखी, नकली बीज-खाद और फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण सोयाबीन की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रही है। मप्र अनाज उत्पादन में पांच कृषि कर्मण अवार्ड पा चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश में सोयाबीन की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। इस कारण किसान अब दूसरी खरीफ फसलों की खेती करने लगे हैं। सोयाबीन बेल्ट माने जाने वाले मालवा इलाके के किसान अब बाजार में उपज की सही कीमत नहीं मिलने से तेजी से इस फसल से मुंह फेर रहे हैं। वहीं 80 के दशक में विंध्य के किसानों की माली हालत सुधारने वाली नकदी फसल सोयाबीन की खेती अब किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। विंध्य प्रदेश के सबसे अधिक सोया उत्पादन वाले सतना जिले में कभी 85 हजार हेक्टेयर में बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल का रकबा घटकर महज 10 हजार हेक्टेयर में सिमट गया है।



### अरबों का काला कारोबार

प्रदेश में हर साल अरबों रुपए के नकली खाद और बीज का कालाकारोबार होता है। नकली खाद-बीज को ब्रांडेड कंपनियों के बारदाने में पैकिंग कर बेचा जाता है। हर साल पुलिस फेविटियों, गोदामों, घरों पर छापामार कर नकली खाद-बीज पकड़ती है। लेकिन उसके बाद भी काला कारोबार चलता रहता है। मप्र में हर साल खाद-बीज की कालाबाजारी होती है। यहां नकली खाद-बीज आसानी से बिक जाता है। इसलिए कंपनियां मप्र पर अपना अधिक फोकस रखती हैं।

### ऐसे होता है खेल

कंपनियां कुछ किसानों को 50 से लेकर 200 रुपए तक का लालच देकर उनसे उनके दस्तावेज और हस्ताक्षर करा कर ये साबित कर देती हैं कि उन्होंने फलां गांव के किसान से बीज को लेकर अनुबंध किया और उनसे बीज की खेती कराई। मगर कंपनियां किसानों से बीज की खेती कराती ही नहीं, बल्कि मंडियों से कम दर पर सोयाबीन खरीद कर उसमें से मोटा दाना अलग करके उसे ही थैलियों में पैक कर और मार्का लगा कर किसानों को प्रमाणित बीज बताकर बेच देती हैं।

### बीज का भाव 9000

मप्र में तीन दशक पहले सोयाबीन यानी पीला सोना के उत्पादन से लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इस बार सोयाबीन के रिपोर्टेड भाव के चलते किसानों को बीज की चिंता सता रही है। दरअसल छह महीने से मंडियों में सोयाबीन के भाव ढाई गुना चल रहे हैं और बीज का भाव 9000 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। इस महीने मानसून की दस्तक होने से पहले किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं।

### इनका कहना है



मप्र में नकली खाद-बीज की कालाबाजारी हो रही है। जानकारी मिलने पर किसान सीधे मुझे शिकायत करें। सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसानों तक खाद-बीज पहुंचने से पहले उसकी पड़ताल कर लें। किसानों के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए। कई नकली कारोबारी पकड़ में आ चुके हैं।

कमल पटेल, कृषि मंत्री सरकार ने तय किया कि किसान को 1200 रुपए में ही प्रति बोरी डीएपी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अनुदान बढ़ा दिया। इसके बाद भी कुछ सहकारी समितियों ने बढ़ी हुई दरों पर किसानों को खाद बेची। इसको लेकर शिकायतें भी मिली हैं। निर्देश दिए हैं कि किसान को 1200 रुपए बोरी से अधिक दर पर खाद नहीं बेची जाएगी, भले ही बोरियों पर दर कुछ भी अंकित हो। पी. नरहरि, प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड)

## मचा हड़कंप: बीज माफिया और डीडीए पर सस्पेंस

# खंडवा: बीज माफिया के सहयोगी पांच अफसरों पर गाज

संवाददाता, खंडवा

प्रदेश के खंडवा जिले में नकली बीज कारोबार की माफिया गैंग के सहयोगी जिले के सभी पांच बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों पर गाज गिरी है। पांचों बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में पांचों अफसर इंदौर स्थित संभागीय कार्यालय में अटैच रहेंगे। इसके आदेश मप्र राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक बीएस धुर्वे ने जारी किए हैं। हाल ही में संभागीय टीम ने जिले के तीन कारोबारियों के यहां छपा मारा था। यहां भारी मात्रा में बीज प्रमाणीकरण के नकली टैग मिले थे। इधर, बीज माफिया बालाजी सीड्स व उत्तम सीड्स के अलावा डीडीए रामस्वरूप गुप्ता पर कार्रवाई बाकी है। कृषि मंत्री के अनुसार कार्रवाई प्रक्रिया में है। किसानों के साथ लगातार हो रही धोखाधड़ी और संभागीय टीम के छापे में नकली बीज के कारोबार का खुलासा होने के बाद भी बीज माफिया व अफसरों पर एक्शन नहीं लिया गया।

**इन पर गिरी गाज:** जिले के प्रभारी एवं उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पीपी सिंह के अलावा सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजाराम बडोले, जयंत कुल्हारे, सुरेश कुमार, अखिलेश चौहान को निलंबित किया गया है। मप्र राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक बीएस धुर्वे ने जारी निलंबन आदेश में बताया कि इन सभी अफसरों द्वारा बीज प्रमाणीकरण कार्यों में लापरवाही बरती गई है।

## इन संस्थाओं पर की थी छापेमार कार्रवाई

गौरतलब है कि हाल ही में एक गोपनीय शिकायत मिलने पर टीम ने खंडवा के ग्राम बावड़िया काजी में बालाजी सीड्स, प्रगति एग्रो सीड्स पांजरिया और उत्तम सीड्स दौदवाड़ा पर छापेमार कार्रवाई की थी। इन संस्थाओं के पास बीजों के नकली टैग बड़ी मात्रा में पकड़ाए थे। कृषि विभाग के अफसरों ने सिर्फ प्रगति एग्रो सीड्स पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं खंडवा जिले में सोयाबीन, कपास व गेहूं के नकली बीज का कारोबार 50 करोड़ रुपए के करीब है।

फिर विवादों में अटल प्रोग्रेस-वे का सर्वे कंपनी ने फीता डाला तो किसान बोले

# पहले आदेश लाओ तब हमारी पुश्तैनी जमीन पर रखना पैर



## इनका कहना है

अटल प्रोग्रेस-वे डवलपमेंट का काम एनएचएआई को देखना है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन को एजेंसी बनाया गया है। प्रोग्रेस-वे की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भोपाल की कंसलटेंसी को दिया है। कंसलटेंसी सर्वे करा रही है। जल्द ही डीपीआर तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही प्रोग्रेस-वे की प्रक्रिया शुरू होगी।

संजय वर्मा, प्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में शासन के आदेश का इंतजार है। जो भी गाइडलाइन और टाइम लाइन मिलेगी उसका पालन कराया जाएगा। जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई तो एनएचएआई के नियमों के मुताबिक की जाएगी।

आशीष सक्सेना, आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना

**संवाददाता, भोपाल।** अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। जब भी सर्वे शुरू होता है किसान विरोध में उतर जाते हैं। दरअसल, कमी जमीन के बदले दोगुना जमीन देने तो कमी एनएचएआई एक्ट के माध्यम से जमीनों के अधिग्रहण की चर्चा सुनकर किसान असमंजस में हैं। अब तो गुस्साए किसानों ने सर्वे कंपनी की टीम के प्रतिनिधियों से यहां तक कह दिया कि हमारी जमीन पर फीता किस अधिकार से लगा रहे हो। पहले मुख्यमंत्री या कलेक्टर का आदेश लाओ तब पुश्तैनी जमीन पर पैर रखना। जमीन के बदले जमीन कहां और कितनी दोगे। दरअसल, मार्च 2022 से पहले अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुरैना जिले के सबलगढ़ के बरोठा से पोरसा के चापक गांव तक शुरू करना है। प्रोग्रेस-वे निर्माण के लिए 72 गांव के 1300 किसानों की 489 हेक्टेयर जमीन उपयोग में ली जाना है। इसलिए राजस्व विभाग की प्राथमिकता किसानों की निजी जमीन के अधिग्रहण की है। हाल ही में भोपाल के कंसलटेंट एलएन मालवीय ग्रुप के सर्वेयर एलाइनमेंट चेक करने के लिए सबलगढ़ के बरोठा गांव पहुंचे तो उन्होंने किसानों की निजी जमीन की नाप-तौल की।

## जमीन के बदले कितनी जमीन कहां मिलेगी

जमीन पर फीता देखकर किसानों ने आपत्ति लेते हुए कहा कि उनसे बिना पूछे जमीन की नाप-जोख क्यों की जा रही है। किसानों को बताया गया कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए रूट की लाइन तैयार की जा रही है। प्रोग्रेस-वे किसानों के खेतों के बीच से निकलेगा इसलिए जमीन को नाप कर देखा जा रहा है। इस पर किसानों ने कहा कि पुश्तैनी जमीन तब तक नहीं देंगे जब तक यह खुलासा नहीं हो जाएगा कि जमीन के बदले कितनी जमीन कहां मिलेगी।

## बरोठा से चापक तक निकलेगा प्रोग्रेस-वे

शुभपुर से भिंड तक जाने वाला अटल प्रोग्रेस-वे मुरैना जिले के सबलगढ़ बार्डर के गांव बरोठा से शुरू होकर कैमाराकलां, अटार, डिगवार खेरा, चिन्नौनी, खांडौली, मसूदपुर, गोरखा, ऐसाह, जौहा, डडौली, रिठौना, रछेड, रुधावली व चापक होता हुआ भिंड पहुंचेगा। चंबल के बीहड़ों को समतल करने पर किसानों के लाखों रुपए खर्च, जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक कोई नीति राजस्व अफसरों को नहीं भेजी, इससे किसान असमंजस में हैं।

## सीएम ने किया था दोगुना जमीन का वादा

सबलगढ़ के घुई गोदोली के किसानों का कहना है कि वह बीहड़ में पट्टे की जमीन 20 साल से जोत रहे हैं। हाईवे उनके खेतों से निकलेगा इसके लिए जमीन के बदले जमीन देने की बात की जा रही है। लेकिन अधिकारी हमारी जमीन तो चिह्नित कर रहे हैं, सरकारी जमीन कहां देंगे, यह बताने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बिना जाने हम अपनी जमीन कैसे व क्यों दें। खांडौली के किसान सरवन सिंह ने बीहड़ की जमीन को समतल करने पर दो लाख रुपए व्यय किए हैं। उनकी जमीन को प्रोग्रेस-वे के लिए अधिग्रहित करने की बात चल रही है। किसान का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में कहा था कि जमीन के बदले किसानों को दो गुना जमीन दी जाएगी। यदि दूनी समतल

जमीन मिलेगी तो ही इस जमीन को सड़क बनाने के लिए दिया जाएगा अन्यथा नहीं। क्योंकि बदले में मिलने वाली जमीन को समतल कराने का खर्चा कौन वहन करेगा। अंबाह के किसान भीकम सिंह तोमर का कहना है कि गांव से सड़क निकलेगी हमें क्या खास फायदा होगा, इसे बताने कोई नहीं आया। राजस्व अधिकारी जमीन देने के लिए सहमति लेने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमारी एक हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या। हम तो कुल 2 हेक्टेयर जमीन के काश्तकार हैं। जमीन के दाम अच्छे मिलेंगे तो जमीन देने पर विचार करेंगे। नकद पैसा मिलेगा उससे और पास में कोई दूसरी सिंचित जमीन खरीद लेंगे।

## अधिग्रहण को लेकर किसान चिंतित

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई को लेकर सबलगढ़ से जौरा विधानसभा क्षेत्र के वह किसान चिंतित हैं, जो बीहड़ की सरकारी जमीन पर बरसों से काबिज होकर खेती कर रहे हैं। उनकी जमीन गई तो बिना कागजातों के ऐसे किसानों को एक्सचेंज में दूसरी जमीन मिलने पर संकट खड़ा होगा। इसलिए किसान अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन देने के मुद्दे पर विरोध की मुद्रा में हैं।

## आदेश के इंतजार में अफसर

309 किमी लंबाई के अटल प्रोग्रेस-वे के लिए पहला काम किसानों की 489 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश हैं कि प्रोग्रेस-वे के लिए किसानों से एक्सचेंज में जमीन ली जाए। किसान जमीन देने की सहमति नहीं देते हैं तो जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए। राजस्व व एनएचएआई के अफसरों का कहना है कि भोपाल से बीते एक साल से अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर कोई आदेश नहीं आया। आदेश आए तो उसका पालन क्रियान्वयन शुरू कराएंगे। संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के संबंध में शासन के आदेश का इंतजार है। उसी के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

# राहत: छोटे किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम जमा करेगी सरकार

संवाददाता, भोपाल

सरकार आत्मनिर्भर मंत्र के रोडमैप पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार का सबसे अधिक फोकस करने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश में किसानों पर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत (पांच एकड़ तक) के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार

दिनों मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी जिसमें यह बात सामने आई है। फसल बीमा योजना के लिए सरकार नई योजना लागू करने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 40 फीसदी किसानों को ही मिलता है। योजना के ऐच्छिक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा नहीं कराते हैं। जब प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होती है तब उन्हें राहत नहीं मिलती है।

## आत्मनिर्भर मंत्र की दिशा में शिवराज का एक और अहम कदम

अपनी ओर से जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में भी आ जाएंगे। अभी छोटी जोत के किसान बीमा कम करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले

आर्थिक सहायता का पूरा बोझ सरकार पर आ जाता है। सरकार ने तय किया है कि योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। ताकि ज्यादा किसान दायरे में आ जाएं। बीमा का दावों का भुगतान भी समय पर हो जाए। किसानों को खरीफ के लिए दो और रबी का बीमा कराने डेढ़ फीसदी प्रीमियम देना होता है।

## छोटे किसानों पर फोकस

दो-तीन एकड़ भूमि वाले किसान यह राशि भी जमा नहीं कर पाते हैं। बीमा योजना का लाभ अधिकांश सक्षम किसान उठाते हैं। जबकि, योजना का मकसद सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करने का है। अब छोटी जोत वाले किसानों का प्रीमियम सरकार जमा करेगी। इससे न सिर्फ योजना का दायरा बढ़ जाएगा बल्कि क्रियान्वयन भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार यह शिकायत आती है कि किसान ने प्रीमियम की राशि जमा कर दी पर बैंकों से वह बीमा कंपनी तक नहीं पहुंचे। ऐसे मामलों के निराकरण में काफी समय लग जाता है। बीमा कंपनियों को किसान के हिस्से के अलावा बीमा प्रीमियम की राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर अनुपात में देती हैं। प्रदेश में लगभग एक करोड़ दो लाख किसान हैं।

## इनका कहना है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने के लिए पिछले साल न सिर्फ वनाधिकार पट्टे वाले किसानों का बीमा कराया गया, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक खुलवाकर प्रीमियम राशि जमा कराई गई थी। पिछले साल आठ लाख 40 हजार किसानों को खरीफ फसल 2018 के लिए एक हजार 921 करोड़ का बीमा दिलाया गया। छह लाख 60 हजार किसानों को रबी फसल 2018-19 के लिए एक हजार 60 करोड़ रुपए का बीमा दिलाया गया। खरीफ फसल 2019 के लिए लगभग 22 लाख किसानों को चार हजार 686 करोड़ रुपए का बीमा दिया गया है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

# पाकिस्तान के रास्ते जून के अंत तक भारत में होगी एंट्री प्रदेश में फिर ईरानी टिड्डी के हमले की आशंका



संवाददाता, भोपाल

मप्र में एक बार टिड्डी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के पास टिड्डी के कुछ समूह पनप रहे हैं। इनके इसी महीने के अंत तक पाकिस्तान में घुसने की आशंका बताई जा रही है। इसके बाद ये राजस्थान के रास्ते भारत में आ सकते हैं। वहां से उनके मप्र में आने की संभावना है। पिछले साल टिड्डी हमले में मप्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि इथोपिया और सोमालिया में इन दिनों हो रही बारिश के चलते बड़ी संख्या में टिड्डियों को पनपने का मौका मिला है। हालांकि अंडों से बाहर निकलते ही इन्हें खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दक्षिण-पश्चिमी ईरान में अनुकूल मौसम के बीच बड़ी संख्या

में टिड्डियों ने अंडे दे रखे हैं। इनमें से हॉपर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इन्हें मारने के लिए ईरान में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

## मानसून में टिड्डियों के लिए अनुकूल होंगी परिस्थितियां

कृषि संगठन का मानना है कि कुछ युवा टिड्डी समूह पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक पाकिस्तान में मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। उस समय इनके लिए आगे बढ़ने की सभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और ये भारत में प्रवेश कर जाएंगे। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में इन्हें पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। ऐसे में उनके मप्र में भी प्रवेश की आशंका जताई जा रही है। संगठन ने

कहा है कि हालांकि इस बार टिड्डियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने का अनुमान है। भारत में टिड्डी दल पाकिस्तान से होकर बाड़मेर-जैसलमेर में प्रवेश करता है। इन दोनों जिलों में प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

## पिछले साल फसलों को पहुंचाया था भारी नुकसान

पिछले साल राजस्थान के रास्ते मप्र में टिड्डियों ने जबरदस्त हमला बोला था। लाखों की संख्या में आए टिड्डी समूहों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इन्हें मारने के लिए पहली बार इंडियन एयर फोर्स तक की मदद लेने की नौबत आ गई थी। बाद में किसानों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला इनका खात्मा किया था।

## भारतीय किसान संघ ने पीएम से लगाई मंडी खोलने की गुहार, लिखा पत्र

# आलू-प्याज के कारोबार में हर दिन 50 करोड़ का नुकसान



संवाददाता, भोपाल

कोरोना कर्फ्यू के कारण लगभग दो महीने से आलू-प्याज मंडी में कामकाज पूरी तरह बंद है। कारोबारियों के बाद अब किसानों का धैर्य भी टूटने लगा है। मई और जून का महीना प्याज और आलू के किसानों के साथ बाजार के लिए भी अहम होता है। बारिश के जोर पकड़ते ही सैकड़ों टन प्याज बर्बाद होना तय है। आलू-प्याज उत्पादक किसानों की ओर से भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राहत मांगी है। इस बीच कारोबारी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अगर मंडी नहीं खोली गई तो प्याज के निर्यात कारोबार में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश में मंडी बंद होने से हर दिन करीब 50 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो रहा है।

## अटक गए सभी आर्डर

मंडी बंद होने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जून प्याज की आवक के लिए सबसे अहम मौका होता है। बांग्लादेश से भी निर्यात मांग निकली हुई है। मंडी बंद है तो निर्यात के आर्डर अटक गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में कारोबार शिप्ट होने लगा है।

## इनका कहना है

उत्पाद किसानों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बीते वर्ष भी लाकडाउन के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। अनजान व्यापारियों से हुए सौदों में मालवा क्षेत्र के किसानों के 50 से 60 लाख अटक गए हैं। वहीं प्रदेशभर में किसानों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है।

दिलीप मुकाती, भारतीय किसान संघ

# मप्र में तेजी से खराब हो रही मिट्टी की सेहत

संवाददाता, भोपाल

जांच और शोध से यह साफ हो गया है कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए। चॉकाने वाला तथ्य यह भी है कि इन दिनों गेहूं, चावल, दाल, ज्वार-बाजरा तथा हरी सब्जी के उपयोग से भी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी विकसित नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए। इसका कारण खेत में अधिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी में 40 फीसदी तक जिंक, आयरन और मैंगनीज की कमी होना है। हर खाद्यान्न में मौजूद यही वे तत्व हैं तो हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में 2020-21 में 4401 मिट्टी के नमूने लिए गए। जांच 12 मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों की हुई।

सर्वाधिक 90 प्रतिशत तक कमी नाइट्रोजन की मिली। इससे पौधों का हरा भाग व दाना नहीं बनता। फॉस्फोरस की कमी 10 प्रतिशत नमूनों में मिली है। इसी कारण पौधे मिट्टी से तत्व नहीं ले पा रहे हैं। पोटैश भी 12 प्रतिशत नमूनों में कम मिली है।

## जिंक, आयरन और मैंगनीज का असर

मिट्टी के 40 प्रतिशत नमूनों में जिंक 0.2 पार्ट्स प्रति मिलियन तक निकला है, जबकि इसका मानक 0.5 से अधिक है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी है। मिट्टी

» अधिक उर्वरकों के उपयोग से 90 प्रतिशत तक नाइट्रोजन घटी

» गेहूं-चावल व दाल में जिंक, आयरन और मैंगनीज की कमी

» खाने वाले लोगों की घट रही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता



के 41 प्रतिशत नमूनों में कमी मिली है। इससे शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। 6 मैंगनीज की मात्रा 36 व सल्फर की मात्रा 6 प्रतिशत नमूनों में कम मिली। इससे तेल वाली फसल हल्की होने से तेल कम मिल रहा है।

## एक जैसी फसल से बचें किसान

विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी की क्वालिटी में आ रही गिरावट का कारण अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग है। हर बार एक जैसी फसल लेना भी दूसरा

कारण है। अनाज वाली फसल के बाद दलहनी फसल लेना चाहिए। किसान को यह भी समझना होगा कि कब किस उर्वरक की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाना है। खेत में जरूरत के मुताबिक जैविक व कछुआ खाद डालना चाहिए तभी मिट्टी में सुधार होगा।

# जनस्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित दुग्ध उत्पादन

## अब पिछड़ों के सहारे नैया

डॉ. विपिन कुमार,  
प्रगती अधिकारी, पशु  
जनस्वास्थ्य एवं महामारी  
विज्ञान विभाग, महु

दुधारू पशुओं के थनों से निकलने वाला प्राकृतिक स्राव है जो कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बीमार से लेकर अपंग, अयोग्यों तक सभी का आदर्श भोज्य पदार्थ है। यह अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक उपयोग होता है। यह स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए। जनस्वास्थ्य की दृष्टि से यह दृश्य धूल, कचरा रहित, रोग जन्य सूक्ष्मजीव रहित, जीवाणु गणना कम, रासायनिक अवशेष रहित (कीटनाशक/प्रतिजीवी/दवाई रहित) तथा मिलावट रहित होना चाहिए। स्वच्छ दूध इसलिए आवश्यक है ताकि उपभोक्ता सुरक्षा, दूषित व खराब गुणवत्ता के कारण आर्थिक क्षति की रोकथाम तथा आगे दुग्ध निर्मित दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध को निर्यात भी किया जा सकता है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जन भी किया जा सकता है। स्वच्छ दुग्ध, एक स्वस्थ गाय अथवा भैंस से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वस्थ जानवर की स्तन ग्रंथि से निकलने वाला दूध सामान्यतः सूक्ष्म जीव रहित होता है। चुचुक नलियों से गुजरने के दौरान इसमें जीवाणु/कीटाणु शामिल होते हैं। दूध दुहने की शुरुआत में बहुत ही अधिक मात्रा में जीवाणु होते हैं। ग्वालियों/दुहने वाले के हाथों, पशुशाला के कार्यों जैसे कि सफाई, ब्रश, चारा डालना, वायु के धूल कण, दूध दुहने के बर्तन आदि के द्वारा भी जीवाणु दूध में विषरित हो सकते हैं। दुग्ध भंडारण के अनुपयुक्त तापमान से दूध में जीवाणुओं की संख्या (सूक्ष्म जीव) में भी वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव, ये बहुत छोटे होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं। मुख्यतः यह जीवाणु, विषाणु एवं फफूंदी आदि होते हैं। जीवाणु, यह दूध में आसानी से वृद्धि करता है। उसकी पौष्टिकता को कम कर सड़ा सकता है। यह दूध को दूषित कर, पीने वाले के शरीर में बुखार, टाइफाइड, जोड़ों का दर्द, इत्यादि परेशानी कर सकता है। विषाणु, वो सूक्ष्मदर्शी है जो दूसरे जीव पर ही जीवित रह सकता है। यह पोलियो, पीलीया, रेबीज, इत्यादि रोग का कारक है। फफूंदी, ये सूक्ष्मदर्शी हारिकारक जहर/पदार्थ दूध में बनाते हैं। कैंसर तक के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दूध को संदूषण से बचाएँ। स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक उपायों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें स्वच्छ पशु आवास, सुरक्षित व पौष्टिक पशुपोषण, स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु और उत्तम दुग्ध दुहन प्रणाली शामिल है।

दुध, एक पूर्ण प्राकृतिक भोजन है। यह दुधारू पशुओं के थनों से निकलने वाला प्राकृतिक स्राव है जो कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बीमार से लेकर अपंग, अयोग्यों तक सभी का आदर्श भोज्य पदार्थ है। यह अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक उपयोग होता है। यह स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए। जनस्वास्थ्य की दृष्टि से यह दृश्य धूल, कचरा रहित, रोग जन्य सूक्ष्मजीव रहित, जीवाणु गणना कम, रासायनिक अवशेष रहित (कीटनाशक/प्रतिजीवी/दवाई रहित) तथा मिलावट रहित होना चाहिए। स्वच्छ दूध इसलिए आवश्यक है ताकि उपभोक्ता सुरक्षा, दूषित व खराब गुणवत्ता के कारण आर्थिक क्षति की रोकथाम तथा आगे दुग्ध निर्मित दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध को निर्यात भी किया जा सकता है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जन भी किया जा सकता है। स्वच्छ दुग्ध, एक स्वस्थ गाय अथवा भैंस से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वस्थ जानवर की स्तन ग्रंथि से निकलने वाला दूध सामान्यतः सूक्ष्म जीव रहित होता है। चुचुक नलियों से गुजरने के दौरान इसमें जीवाणु/कीटाणु शामिल होते हैं। दूध दुहने की शुरुआत में बहुत ही अधिक मात्रा में जीवाणु होते हैं। ग्वालियों/दुहने वाले के हाथों, पशुशाला के कार्यों जैसे कि सफाई, ब्रश, चारा डालना, वायु के धूल कण, दूध दुहने के बर्तन आदि के द्वारा भी जीवाणु दूध में विषरित हो सकते हैं। दुग्ध भंडारण के अनुपयुक्त तापमान से दूध में जीवाणुओं की संख्या (सूक्ष्म जीव) में भी वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव, ये बहुत छोटे होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं। मुख्यतः यह जीवाणु, विषाणु एवं फफूंदी आदि होते हैं। जीवाणु, यह दूध में आसानी से वृद्धि करता है। उसकी पौष्टिकता को कम कर सड़ा सकता है। यह दूध को दूषित कर, पीने वाले के शरीर में बुखार, टाइफाइड, जोड़ों का दर्द, इत्यादि परेशानी कर सकता है। विषाणु, वो सूक्ष्मदर्शी है जो दूसरे जीव पर ही जीवित रह सकता है। यह पोलियो, पीलीया, रेबीज, इत्यादि रोग का कारक है। फफूंदी, ये सूक्ष्मदर्शी हारिकारक जहर/पदार्थ दूध में बनाते हैं। कैंसर तक के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दूध को संदूषण से बचाएँ। स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक उपायों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें स्वच्छ पशु आवास, सुरक्षित व पौष्टिक पशुपोषण, स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु और उत्तम दुग्ध दुहन प्रणाली शामिल है।

हवा का पर्याप्त आवागमन होना चाहिए। गोबर एवं पेशाब की उचित निकासी (कम से कम 2 बार) होना चाहिए। गोबर एवं कचरे के पुनःचक्रण के लिए गोबर गैस प्लांट का निर्माण करना चाहिए जिससे न सिर्फ वातावरण साफ होगा, बल्कि पुनःचक्रण द्वारा ईंधन व खाद की प्राप्ति तथा धन की बचत होगी।

**सुरक्षित एवं पौष्टिक पशु पोषण:** पशु को सुरक्षित एवं पोषक पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ ही स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध भी प्राप्त होगा। पशु को बचा हुआ अथवा बासी आहार न दें। जो कि कवक वृद्धि, फफूंदी का कारक बनता है। जहर पैदा करता है। यह जहर अप्लेटॉक्सिन, दूध द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर बीमारी का कारण बनता है। पशु का चारा, दाना एवं पानी कीटनाशक रहित होना चाहिए। क्योंकि यह कीटनाशक भी दूध के द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर दुष्प्रभाव करता है। स्वच्छ एवं ताजा पानी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है।

**सुरक्षित पशु आहार:** सुरक्षित पशुजन्य उत्पाद (दूध, इत्यादि)। **स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु:** पशु को दूध दुहने से पहले हमेशा साफ पानी द्वारा नहलाएं एवं स्वच्छ करें। नियमित रूप से संक्रामक बीमारियों के लिए जांच करवाएं। बीमार पशुओं का समय पर ठीक से इलाज करवाएं। पशुस्वस्थता के लिए समय-समय पर टीकाकरण करवाएं। बीमार पशु के दूध का उपयोग न करें। जिन पशुओं को एंटीबायोटिक अथवा अन्य दवाई दी गई है। उनके दूध को हटा दें। वापसी अवधि का पालन करें ताकि उनके अवशेष दूध में न आएँ एवं दुग्ध उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। यदि पशु स्वच्छ एवं स्वस्थ रहेगा तो किसानों को भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा।

**उत्तम दुग्ध दुहन प्रणाली:** दूध दुहने से पहले दुग्धशाला को साफ करें। हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार धोएं। जानवर के थनों को साफ पानी से धोएं व थनों के दुहने उपरांत उन्हें धोकर एन्टिसेप्टिक का उपयोग, चूचक डिप तकनीक द्वारा करें। अधिक दूध देने वाली नस्तों में चूचक आवरण, मर्ज बंचक का उपयोग (टेप लगाकर) करें इससे थन स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ दूध के साथ-साथ थनेला रोग से बचाव भी होगा। दूध दुहने का सही तरीका फुल हैंड मिलकिंग ही प्रयोग में लाएं। दूध दुहने के शुरुआत में पहले कुछ दूध को हटा दें। क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीवों की संख्या अत्यधिक होती है। दूध एकत्रित करने के लिए साफ स्वच्छ एवं सूखे बर्तन का उपयोग करें। दूध को ढककर रखें। दूध दुहने की प्रक्रिया सात मिनट के अंदर पूरी करें। थनों में दूध न छोड़े नहीं तो जीवाणु पनपने का खतरा रहता है। थनैला रोग हो सकता है। ग्वाला/दूधिये का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। बीमार व्यक्ति को दुग्ध दुहन कार्य एवं अन्य कार्यों से दूर रखें। दूध द्वारा उसकी बीमारी अन्य व्यक्तियों को भी हो सकती है। दूधिये के हाथ पैर साफ, कपड़े साफ, नाखून व दाढ़ी कटे हुए होने चाहिए। दूध दुहने के समय तम्बाकू/धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। पालतू कुत्ता/बिल्ली/अन्य पशु को दूध दुहते समय दूर रखना चाहिए। उपरोक्त उपायों को अमल में लाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही स्वस्थ पशु एवं समृद्ध किसान की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

स्वच्छ पशु आवास: स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए पशु आवास की स्वच्छता बहुत जरूरी है। पशुशाला में मक्खियाँ, मच्छर एवं अन्य कीट होते हैं जो कि संक्रामक बीमारियाँ पैदा करते हैं। यदि आवास की वातायन/वायु संचालन व्यवस्था ठीक नहीं है तो मेटाबोलिक गैसों जैसे मैथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, अमोनिया आदि पशु स्वास्थ्य एवं मानव (ग्वाला) स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि पशु आवास स्वच्छ नहीं है तो जीवाणु, दूध दुहने के समय दूध को दूषित कर पनपने लगते हैं। पशु आवास का फर्श पक्का होना चाहिए। फर्श को नियमित रूप से साफ कर सेनिटाइज (कीटाणुनाशक द्वारा) किया जाना चाहिए।



हवा का पर्याप्त आवागमन होना चाहिए। गोबर एवं पेशाब की उचित निकासी (कम से कम 2 बार) होना चाहिए। गोबर एवं कचरे के पुनःचक्रण के लिए गोबर गैस प्लांट का निर्माण करना चाहिए जिससे न सिर्फ वातावरण साफ होगा, बल्कि पुनःचक्रण द्वारा ईंधन व खाद की प्राप्ति तथा धन की बचत होगी।

**सुरक्षित एवं पौष्टिक पशु पोषण:** पशु को सुरक्षित एवं पोषक पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ ही स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध भी प्राप्त होगा। पशु को बचा हुआ अथवा बासी आहार न दें। जो कि कवक वृद्धि, फफूंदी का कारक बनता है। जहर पैदा करता है। यह जहर अप्लेटॉक्सिन, दूध द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर बीमारी का कारण बनता है। पशु का चारा, दाना एवं पानी कीटनाशक रहित होना चाहिए। क्योंकि यह कीटनाशक भी दूध के द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर दुष्प्रभाव करता है। स्वच्छ एवं ताजा पानी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है।

**सुरक्षित पशु आहार:** सुरक्षित पशुजन्य उत्पाद (दूध, इत्यादि)। **स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु:** पशु को दूध दुहने से पहले हमेशा साफ पानी द्वारा नहलाएं एवं स्वच्छ करें। नियमित रूप से संक्रामक बीमारियों के लिए जांच करवाएं। बीमार पशुओं का समय पर ठीक से इलाज करवाएं। पशुस्वस्थता के लिए समय-समय पर टीकाकरण करवाएं। बीमार पशु के दूध का उपयोग न करें। जिन पशुओं को एंटीबायोटिक अथवा अन्य दवाई दी गई है। उनके दूध को हटा दें। वापसी अवधि का पालन करें ताकि उनके अवशेष दूध में न आएँ एवं दुग्ध उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। यदि पशु स्वच्छ एवं स्वस्थ रहेगा तो किसानों को भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा।

**उत्तम दुग्ध दुहन प्रणाली:** दूध दुहने से पहले दुग्धशाला को साफ करें। हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार धोएं। जानवर के थनों को साफ पानी से धोएं व थनों के दुहने उपरांत उन्हें धोकर एन्टिसेप्टिक का उपयोग, चूचक डिप तकनीक द्वारा करें। अधिक दूध देने वाली नस्तों में चूचक आवरण, मर्ज बंचक का उपयोग (टेप लगाकर) करें इससे थन स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ दूध के साथ-साथ थनेला रोग से बचाव भी होगा। दूध दुहने का सही तरीका फुल हैंड मिलकिंग ही प्रयोग में लाएं। दूध दुहने के शुरुआत में पहले कुछ दूध को हटा दें। क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीवों की संख्या अत्यधिक होती है। दूध एकत्रित करने के लिए साफ स्वच्छ एवं सूखे बर्तन का उपयोग करें। दूध को ढककर रखें। दूध दुहने की प्रक्रिया सात मिनट के अंदर पूरी करें। थनों में दूध न छोड़े नहीं तो जीवाणु पनपने का खतरा रहता है। थनैला रोग हो सकता है। ग्वाला/दूधिये का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। बीमार व्यक्ति को दुग्ध दुहन कार्य एवं अन्य कार्यों से दूर रखें। दूध द्वारा उसकी बीमारी अन्य व्यक्तियों को भी हो सकती है। दूधिये के हाथ पैर साफ, कपड़े साफ, नाखून व दाढ़ी कटे हुए होने चाहिए। दूध दुहने के समय तम्बाकू/धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। पालतू कुत्ता/बिल्ली/अन्य पशु को दूध दुहते समय दूर रखना चाहिए। उपरोक्त उपायों को अमल में लाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही स्वस्थ पशु एवं समृद्ध किसान की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

स्वच्छ पशु आवास: स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए पशु आवास की स्वच्छता बहुत जरूरी है। पशुशाला में मक्खियाँ, मच्छर एवं अन्य कीट होते हैं जो कि संक्रामक बीमारियाँ पैदा करते हैं। यदि आवास की वातायन/वायु संचालन व्यवस्था ठीक नहीं है तो मेटाबोलिक गैसों जैसे मैथेन, कार्बन डाईऑक्साइड, अमोनिया आदि पशु स्वास्थ्य एवं मानव (ग्वाला) स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि पशु आवास स्वच्छ नहीं है तो जीवाणु, दूध दुहने के समय दूध को दूषित कर पनपने लगते हैं। पशु आवास का फर्श पक्का होना चाहिए। फर्श को नियमित रूप से साफ कर सेनिटाइज (कीटाणुनाशक द्वारा) किया जाना चाहिए।

पंजाब की सियासत में घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह समाप्त नहीं हुई थी कि अब अकाली दल ने नया सियासी दांव चलकर सभी को चौंका दिया। दशकों तक हिंदुत्ववादी पार्टी संग चुनाव लड़ने वाली पार्टी अचानक से बसपा के साथ गठबंधन कर सियासी गलियारों में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। आगामी चुनावों को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ने मायावती से हाथ मिलाकर राज्य के पिछड़े और दलित वोटों पर अपना कजा जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में दलितों का 32 फीसदी से ज्यादा वोट फीसदी से ज्यादा वोट अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव जीतने के बाद दलित उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी। सुखबीर सिंह बादल को यह बात अच्छी तरह से पता है कि दलितों के समर्थन के बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है। दरअसल, राज्य में अकाली दल को साा चलाने का पुराने अनुभव रहा है। लंबे समय तक पंजाब की साा का स्वाद चख चुकी पार्टी को भरोसा है कि दलित वोट बैंक को साध लिया जाता है तो अगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसीलिए अकाली दल ने दलित और पिछड़ों के हिमायती नेता को साथ रखकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। अकाली दल ने वर्ष 2007-2012 के चुनावों में जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों इसी दल के नेता बने थे। बाद में अकाली दल ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर साा में वापसी की, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दों पर अकाली दल भाजपा से अलग हो गई। अब पंजाब के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार यानी सुखबीर सिंह बादल को बसपा से गठबंधन करना कितना रास आएगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि राज्य में एक तिहाई से ज्यादा दलितों और पिछड़ों का वोटबैंक चुनावी नतीजों के बदलने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। राज्य में अनुसूचित जातियों की अच्छी खासी संख्या है। अकाली दल को यह पता है कि साा पाने के लिए 40 फीसदी से ऊपर वोट प्रतिशत होनी चाहिए, अगर इससे कम तो साा पाना मुश्किल होगा। देश में पंजाब में दलितों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, आबादी का कुल 32 फीसदी दलित राज्य में हैं, लेकिन आज तक पंजाब के राजनीतिक इतिहास में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। जानकार बताते हैं कि इसकी मुय वजह दलितों का आपस में तालमेल नहीं होना है। यहाँ का दलित बंट्टा हुआ है। कुछ तबकों की वफादारी अकाली दल की ओर है तो कुछ का झुकाव कांग्रेस की ओर। पंजाब में यह एकजुट होकर कभी नहीं रहे। बसपा लगातार सियासी जमीन खोती जा रही है।

## हरित शहरों की ओर

वर्ष 1974 से ही हर वर्ष पांच जून को दुनिया भर के राष्ट्र, समुदाय और व्यक्ति विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए हमारी धरती और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण करने के लिए एकजुट होते आए हैं। इस वर्ष 'इकोसिस्टम की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक' का शुभारंभ किया जा रहा है, ताकि इस दशक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इस दशक के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाते हुए इस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक' का शुभारंभ किया गया है। चूंकि विकास की बाध्यताएँ बढ़ी हैं, इसलिए इसी के अनुरूप हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी हरे और स्वस्थ भविष्य के अनुकूल बनाने की क्षमता की आवश्यकता है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 सतत विकास लक्ष्यों के मुय प्रयोजनों में से एक है। इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने

के लिए एकजुटता वाले व्यापक दृष्टिकोण को मोदी सरकार के पिछले सात वर्षों के दौरान हुए भारत के नीतिगत और राजनीतिक विचार-विमर्श में शामिल किया गया है। एजेंडा 2030 का आदर्श सिद्धांत: सतत विकास लक्ष्य-किसी को भी पीछे न छोड़ें अंत्योदय के माध्यम से गांधी जी के सर्वोदय के दर्शन अर्थात् सुदूर तक सबसे पहले पहुंच के सार को काफी हद तक साकार रूप देता है। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भारतीय विचार और नीति का हिस्सा रहा है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अभियानों के निष्पादन में एक मूलभूत विशेषता भी रही है। 15 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता (स्वच्छ भारत) आंदोलन का शुभारंभ किया था। वास्तव में, यह हमारे शहरी परिदृश्य के पूरी तरह से बदलावकी एक अग्रगामी पहल थी। दुनिया

में कहीं भी संचालित किए गए व्यापक शहरीकरण कार्यक्रम को तौर पर जून 2015 में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख अभियानों के माध्यम से-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन (अमृत) और स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) का शुभारंभ किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रमुख अभियानों की शुरुआत 2016 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने से

एक वर्ष पहले की थी। इसके बावजूद भी, सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही है कि अधिकतर एसडीजी इन प्रमुख अभियानों के मुय उद्देश्यों में स्पष्ट नजर आते हैं। इन राष्ट्रीय अभियानों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जबकि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सतत विकास को सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) खुले में शौच से मुक्त भारत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का निर्माण और समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद इस नागरिक नेतृत्व वाले जन आंदोलन की प्रेरक शक्ति बन गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि एसबीएम-यू के तहत की गई विभिन्न पहलों से 2022 तक जीएचजी उत्सर्जन की 17.42 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा

को कम किया जा सकता है। स्मार्ट शहर अभियान हमारे शहरों में शासन, स्थिरता और आपदा जोखिम जैसी स्थितियों में सुधार के लिए तकनीकी प्रगति का कार्यभार संभाल रहा है। हमारे शहरी केंद्रों में ऊर्जा दक्षता और गैर-मोटर चालित परिवहन क्षमता में सुधार के लिए स्मार्ट समाधान लागू किए जा रहे हैं। हमारे शहरों के जलवायु-संबंधित विकास को आगे बढ़ाने के लिए, लाइमेट स्मार्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इस प्रारूप का उद्देश्य शहरों को हरित, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल शहरी आवासों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च कार्य प्रणालियों को अपनाना, सहयोग करना और इनका आदान-प्रदान करने में मदद करना है। अब तक, 417.5 किलोमीटर स्मार्ट सड़कों के लिए बुनियादी ढांचा, 30 मेगावाट पैदा करने वाले सौर पैनल, 253.5 एमएलडी अपशिष्ट जल शोधन क्षमता का कार्य पूरा हो चुका है।

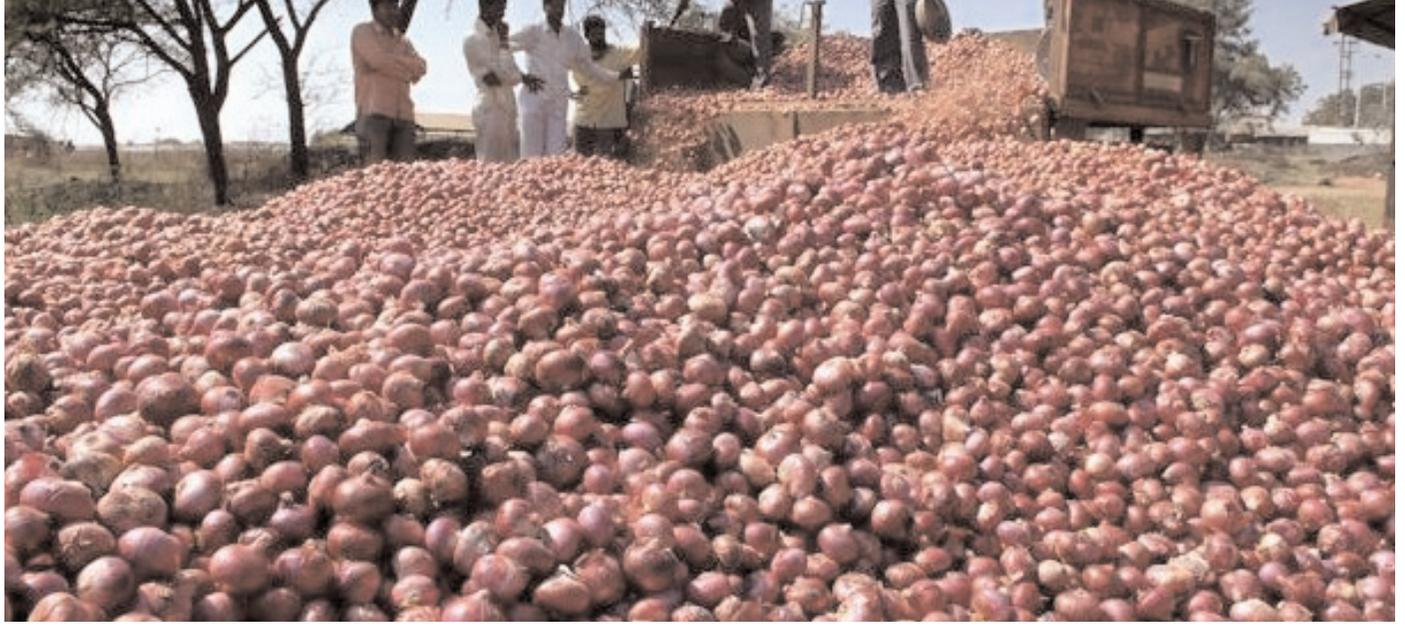


» खरीफ प्याज योजना किसानों के लिए वरदान » मध्य प्रदेश के 25 जिलों में योजना लागू

# प्याज की खेती पर मिलेगी 40 % सब्सिडी

संवाददाता, भोपाल

अधिकतर खाने-पीने की चीजों में प्याज का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि प्याज की डिमांड सालभर बनी रहती है। इसी मांग को पूरी करने के लिए खरीफ सीजन में भी प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वहीं सरकार भी खरीफ सीजन में प्याज की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। दरअसल, प्याज उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए एक योजना लेकर आई है। जिसके तहत राज्य के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना को खरीफ प्याज योजना का नाम दिया गया है।



## खरीफ प्याज योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। योजना के तहत खरीफ सीजन में हाइब्रिड (संकर) प्याज की खेती करने वाले किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश के 25 जिलों में लागू है। जिसके अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को खर्च का 40 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। यह योजना प्रदेश के उन किसानों के लिए है जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम जमीन है।

## 25 जिलों को मिलेगा लाभ

योजना के लिए मध्य प्रदेश के 25 जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ

प्रदेश के राजगढ़, रायसेन, हरदा, बैतूल, शाजापुर, गुना, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, अशोकनगर, खरगोन, उज्जैन, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, आगर मालवा, मंदसौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, डिंडोरी और दमोह जिले के किसान उठा सकते हैं।

## 50 हजार तक का अनुदान

इस योजना के तहत हाइब्रिड प्याज की खेती पर 40

प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 50 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं आवेदक को 20 हजार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाता है।

## जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, खसरा नंबर/बी-1 की प्रति और जाति प्रमाण पत्र देना होगा।

## यहां करें आवेदन

किसानों को खरीफ सीजन में हाइब्रिड प्याज की खेती के लिए यह अनुदान दिया जाता है। इसके लिए 7 जून 2021 से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन उद्यानिकी विभाग मप्र फार्मर्स सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम <https://mpfstts.mp.gov.in/mphd/#/> के जरिये किया जा सकता है।

## अच्छे उत्पादन के लिए किसान अपनाएं यह पद्धति

# ग्रीनहाउस टमाटर की खेती कर देगी मालामाल



संवाददाता, भोपाल

कभी मौसम की मार तो कभी विभिन्न व्याधियों के चलते किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी ने विकास किया है कृषि तकनीक भी उतनी ही समृद्ध होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न कीट व्याधियों से फसल को बचाने में ग्रीनहाउस तकनीक बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रीनहाउस तकनीक से खेती आसानी से की जा सकती है। इस तकनीक से सब्जियों को उगाना भी बेहद आसान हो गया है। टमाटर की खेती ग्रीनहाउस में आसानी से की जा सकती है।

**अनुमानित खर्च:** अधिक वर्षा, गर्मी, वायरस या कीटों आदि प्रकोप जैसी परिस्थितियों में भी इस प्रक्रिया से टमाटर की खेती की जा सकती है। जहां ग्रीनहाउस में खर्च की बात की जाए तो इसके निर्माण के

लिए एक वर्गमीटर के लिए 700 से 1000 रुपए तक का खर्च आता है। ग्रीनहाउस तकनीक में निम्न दबाव के साथ सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए डेढ़ से दो मीटर ऊंचे स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण कर पानी दिया जाता है। जिससे फसल और सब्जियों में आसानी से सिंचाई की जा सकती है।

**उपयुक्त किस्में:** ग्रीनहाउस में टमाटर की खेती के लिए ऐसी किस्मों को चयन करना चाहिए जिनके फल का वजन 100 से 120 ग्राम तक हो। इसके लिए पूसा दिव्या, लक्ष्मी, डीएआरएल-303, अर्का सौरभ, अविमन, अर्का रक्षक, पंत बहार जैसी किस्में उपयुक्त हैं। पूसा चेरी टमाटर की खेती ग्रीनहाउस में विशेषतौर पर की जाती है।

**अपेक्षित तापमान:** यह ऐसी तकनीक है जिसमें सब्जियों, फसलों और फलों को लंबी अवधि के लिए उगाया जा सकता है। गौरतलब

है कि ग्रीनहाउस में टमाटर की प्रोथ के लिए रात का तापमान अनुकूल होना आवश्यक है। अच्छे उत्पादन के लिए निम्न तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान 16-22 डिग्री सेल्सियस उचित माना जाता है।

**ऐसे तैयार करें नर्सरी :** ग्रीनहाउस में टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई बेंड तैयार करना चाहिए। बीजों की बोवनी के 20 से 25 दिनों बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों की रोपाई हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। टमाटर के पौधों को 20 दिनों बाद 8 फीट ऊंचे ओवरहेड तारों से लिपटी हुई रस्सियों से बांधा जाता है। ग्रीनहाउस में 1000 हजार वर्गमीटर में 2400 से 2600 टमाटर पौधों की जरूरत पड़ती है।

**सिंचाई, खाद-उर्वरक:** ग्रीनहाउस में टमाटर की खेती के लिए घुलनशील उर्वरकों को 5:3:5 के अनुपात में दिया जाता है। जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिश्रित होता है। वहीं सिंचाई की बात की जाए तो गर्मी के दिनों में एक सप्ताह में तीन बार तथा ठंडी के दिनों में सप्ताह में दो बार सिंचाई की जाती है।

**उत्पादन:** टमाटर की फसल 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। जहां तक उत्पादन की बात करें तो 1000 वर्गमीटर से 10 से 15 टन टमाटर का उत्पादन होता है। वहीं टमाटर की चेरी किस्म का उत्पादन कम होता है। इस किस्म से एक हजार वर्गमीटर से 2 से 3 टन टमाटर का उत्पादन होता है।

## किसान होंगे खुशहाल: कम पानी में अच्छा उत्पादन

# मप्र में सरसों की नई किस्म में मिलेगा 50 फीसदी तेल



प्रवीन नामदेव, जबलपुर

शहर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार की गई सरसों की नई किस्म अब किसानों के लिए लाभ का धंधा बनेगी। सरसों की नई वैरायटी 'आरवीएम-2' न केवल उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होगी, बल्कि यह असिंचित क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। नई वैरायटी को जिले में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। यह वैरायटी प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वैरायटी में सरसों के एक दाने से 50 फीसदी तक तेल निकलता है। अभी तक फसलों में केवल 30 से 35 फीसदी ही तेल निकाला जा सकता था।

## कम पानी वाले क्षेत्रों में प्रभावी

कृषि वैज्ञानिकों ने 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की इस प्रजाति को तैयार किया है। साथ ही किसानों को भी प्रेक्टिकल रूप से इसे बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जबलपुर के कुंडम, शहपुरा,

पानगर तहसील जहां पानी का संकट है, वहां सरसों की इस नई वैरायटी को आसानी से लगाया सकता है। यह संचित और असंचित दोनों ही जगह कारगर साबित होगी। जिले में सरसों की खेती का रकबा करीब 35 हेक्टेयर है। जिसे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं।

## इनका कहना है

सरसों की नई वैरायटी में पचास फीसदी से अधिक तेल मिलता है। यह वैरायटी मप्र को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसे लगाकर एक साथ दोहरा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हम मॉडल के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

- डॉ. एके सिंह, कृषि वैज्ञानिक,

जबलपुर कृषि विवि किसानों को फसल की खूबियों के बारे में परिचित कराने के साथ ही इस मॉडल में खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के किसानों को सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। सरसों की नई किस्म किसानों को मालामाल कर देगी।

डॉ. डीके सिंह, कृषि वैज्ञानिक, जबलपुर कृषि विवि

# इफको ने शुरू किया नैनो तरल यूरिया का उत्पादन

» यूपी व गुजरात के किसानों को मिलेगी पहली खेप

» 2023 तक 1.37 करोड़ टन यूरिया की जगह लेगी

» तरल यूरिया का किसानों की लिए पहला ट्रक रवाना



भोपाल/नई दिल्ली

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड, इफको ने नैनो तरल यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नैनो यूरिया तरल की अपनी पहली खेप किसानों के उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश भेजी। इफको नैनो यूरिया तरल एक नया और अनोखा उर्वरक है, जिसे दुनिया में पहली बार इफको द्वारा गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इफको की पेटेंटेड तकनीक से विकसित किया गया है। इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की 50वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान इस उत्पाद को दुनिया के सामने पेश किया। इसकी पहली खेप को गुजरात के कलोल से रवाना किया गया।

## बोतल के लिए 240 रुपए तय

गुजरात के कलोल और उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर की इफको की इकाइयों में नैनो यूरिया संयंत्र के निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू किया जा चुका है। तरल नैनो यूरिया अभी बाजार में नहीं आया है, लेकिन इफको ने किसानों के लिए नैनो यूरिया का मूल्य 500 मिली के बोतल के लिए 240 रुपए तय किया है जो कि बोरी में आने वाली यूरिया से लगभग 11 प्रतिशत कम है।

## ईको-फ्रेंडली नैनो यूरिया

लीचिंग और गैसीय उत्सर्जन के जरिये खेतों से हो रहे पोषक तत्वों के नुकसान से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ रहा है। इसे नैनो यूरिया के प्रयोग से कम किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई अवशिष्ट

प्रभाव नहीं है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82 प्रतिशत हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान यूरिया की खपत 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। यूरिया के लगभग 30-50 प्रतिशत नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है और बाकी लीचिंग, वाष्पीकरण और रन ऑफ के परिणामस्वरूप त्वरित रासायनिक परिवर्तन के कारण बर्बाद हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता कम हो जाती है।

## नैनो यूरिया कारगर विकल्प

यूरिया के अतिरिक्त उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड नामक ग्रीनहाउस गैस बनता है। जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। नैनो यूरिया तरल पर्यावरण हितैषी, उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता वाला एक अनोखा उर्वरक है जो लंबे समय में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में एक टिकाऊ समाधान है, क्योंकि यह नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है। मृदा, वायु एवं जल निकायों को दूषित नहीं करता है। ऐसे में यह पारंपरिक यूरिया का एक कारगर विकल्प है।

## नैनो यूरिया लाभकारी

इफको नैनो यूरिया के एक कण का आकार लगभग 30 नैनोमीटर होता है। सामान्य यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठ क्षेत्र और आयतन अनुपात लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, अपने अति-सूक्ष्म आकार और सतही विशेषताओं के कारण नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़के जाने से पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों के जिन भागों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वे कण वहां पहुंचकर संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

## कम मात्रा, ज्यादा लाभ

सामान्य यूरिया के प्रयोग से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं जैसे ग्रीनहाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया उत्सर्जन, मृदा अम्लीकरण तथा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन आदि के समाधान में नैनो यूरिया तरल पूर्णतः सक्षम है। पौधे की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य यूरिया उर्वरक की तुलना में इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है।

## बढ़ेगा फसल का उत्पादन

आईसीएआर के अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर 11,000 से अधिक स्थानों और 40 से अधिक फसलों पर कराए गए प्रभावकारिता परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि नैनो यूरिया न केवल फसल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि यह सामान्य यूरिया की आवश्यकता को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है। यही नहीं, नैनो यूरिया के उपयोग से उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

## इफको का लक्ष्य

इफको ने यह उम्मीद जताई है कि नैनो यूरिया के आने से दाने वाली यूरिया के उपयोग में कमी आएगी। इफको का लक्ष्य है दाने वाले यूरिया के उपयोग में 50 प्रतिशत की कमी करना है। वर्ष 2023 तक 13.7 मिलियन टन दानेदार यूरिया के बराबर नैनो यूरिया लाया जाएगा।

## कृषि क्रांति लाने की क्षमता

नैनो यूरिया तरल का प्रयोग अनुशंसित स्तरों पर मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों, प्रकंद जीवों और पर्यावरण के लिए

## इनका कहना है

देश में उपयोग होने वाले उर्वरकों में यूरिया का स्थान पहले नंबर पर है। नाइट्रोजन खपत में 82 प्रतिशत स्थान यूरिया का है। यूरिया की खपत बढ़ रही है। 2020-21 के दौरान यूरिया की खपत 3.7 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019-20 में 33.526 मिलियन टन यूरिया की खपत है। 24.45 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन किया जाता है, जबकि 9.123 मिलियन टन आयात किया जाता है।

सदानंद गौड़ा, केंद्रीय, रसायन और उर्वरक मंत्री लिक्विड तरल यूरिया का पहला ट्रक किसानों को आपूर्ति के लिए डिस्पैच भी किया जा चुका है। प्रथम चरण में 14 करोड़ बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता विकसित की जा रही है। दूसरे चरण में वर्ष 2023 तक अतिरिक्त 18 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष 2023 तक ये 32 करोड़ बोतलें संभवतः 1.37 करोड़ टन यूरिया की जगह लेंगी।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको इफको नैनो यूरिया 21वीं सदी का उत्पाद है। आज के समय की जरूरत है कि हम पर्यावरण, मृदा, वायु और जल को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। गुजरात के कलोल एवं उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर स्थित इफको की इकाइयों में नैनो यूरिया संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

दिलीप संघाणी, उपाध्यक्ष, इफको

पूरी तरह सुरक्षित है। इफको नैनो यूरिया सतत कृषि और खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सटीक और सुव्यवस्थित कृषि की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। इसमें पूरी दुनिया में कृषि क्रांति लाने की क्षमता है।

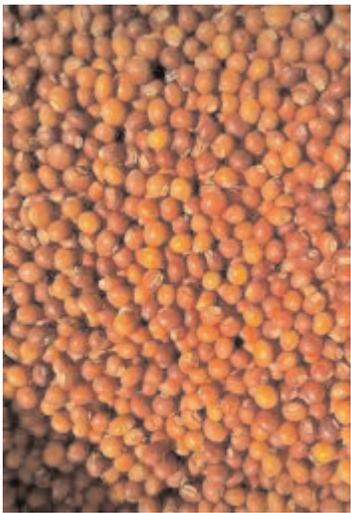
## कैसे मिलेगा किसानों सरकारी बीज

# भरी उदासीनता: मप्र में अभी तक समितियों ने नहीं की मांग

**-बाजार में सोयाबीन का अप्रमाणित बीज बिक रहा 9 हजार क्विंटल**

संवर्द्धता, भोपाल

खरीफ फसल की बोवनी की तैयारियों में किसान जुट गए हैं और बीज, खाद की खरीदी करने लगे हैं, लेकिन सरकारी बीज अभी तक नहीं आया है। सरकारी बीज सहकारी समितियों से मिलता है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मांग ही नहीं की गई है, जिससे किसान महंगे दामों पर बाजार से अप्रमाणित बीज खरीद रहे हैं। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संकट के बाद भी खरीफ की फसल की बोवनी तेजी पर है।



अगर बात पिछले साल खरीफ की बुवाई से करें तो इस बार रकवा 16.4 फीसदी बढ़ चुका है। पिछले साल 67.8 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवनी हुई थी। वहीं मप्र में खरीफ फसल की बोवनी की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसल के कारण बीज का संकट किसानों के सामने खड़ा है।

## लुट रहे किसान

सरकारी बीज की स्थिति यह है कि सरकारी समितियों द्वारा अभी तक मांग ही नहीं भेजी गई है और यदि अब मांग आती भी है तो बीज कब आएगा इसका भरोसा नहीं है। मजबूरी में किसान बाजार से 8 से 9 हजार रुपए क्विंटल में बीज खरीद रहे हैं। बाजार में मिलने वाला बीज प्रमाणित भी नहीं है,

जिससे कई बार अफलन जैसी स्थिति भी बन जाती है। वहीं उड़द का बीज भी किसानों को आठ हजार रुपए क्विंटल में मिल पा रहा है।

## बढ़ रही खेती में लागत

किसान राममिलन ने बताया कि बीज, खाद, डीजल के दाम बढ़ने से दिनों-दिन खेती की लागत बढ़ती जा रही है और फसल आएगी या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के चलते पिछले दो वर्षों से खरीफ फसल खराब हो रही है। बाजार में सोयाबीन बीज 9 हजार रुपए क्विंटल में मिल रहा है, जबकि सरकारी बीज के दाम 7500 रुपए क्विंटल है और वह प्रमाणित भी रहता है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है।

# सोयाबीन की दूसरी किस्मों की बोवनी करें किसान

वेबीनार में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह और बताए फायदे



संवाददाता, इंदौर

विगत दो सालों से खराब मौसम के कारण सोयाबीन के बीजोत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति में कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश के किसानों को अपने पास उपलब्ध सोयाबीन किस्म जेएस 95-60 की गुणवत्ता में कमी आने के कारण सोयाबीन की अन्य वैकल्पिक किस्मों की खेती करनी चाहिए। यह बात भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉ. नीता खांडेकर ने उपसंचालक कृषि, जिला इंदौर के सहयोग से गत दिनों भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा सोयाबीन की शीघ्र, मध्यम एवं अधिक समयावधि वाली किस्मों तथा उनकी बीज उपलब्धता विषय पर आयोजित एक वेबिनार के दौरान कही। वेबिनार में इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के किसानों और विस्तार कर्मियों ने भाग लिया। वहीं इंदौर सांसद शंकर

लालवानी ने सोयाबीन की फसल में आ रही कीट एवं व्याधियों की समस्याओं और इसके लिए संस्थान द्वारा सोयाबीन खेती की निरंतर विकसित उत्पादन तकनीक एवं नवीनतम पद्धतियों के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

## किसान ऐसे करें प्रयोग

उपसंचालक कृषि, एसएस राजपूत ने सभी शासकीय एवं निजी बीज कंपनियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान हमेशा सोयाबीन बीज अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। जबकि आईआईएसआर की अनुशंसा के अनुसार किसानों को सोयाबीन के बीज का न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकुरण के आधार पर 60-80 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे बीज की कमी की समस्या का भी

कुछ हद तक निराकरण किया जा सके।

## बीज अंकुरण परीक्षण जरूरी

सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के डॉ. मृणाल कुचलन ने किसानों को रेत से भरी ट्रे का उपयोग करते हुए सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण करने का सरल उपाय बताया। साथ ही डॉ. अमरनाथ शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) एवं अध्यक्ष पौध संरक्षण विभाग द्वारा सोयाबीन की फसल में पीले मोजेक बीमारी, सफेद मक्खी एवं अन्य कीटों के नियंत्रण करने का वैज्ञानिक तरीका बताया। उन्होंने सोयाबीन की फसल में उचित कीट प्रबंधन के लिए समेकित कीट प्रबंधन के अन्य तरीके जैसे पीली चिपचिपी पट्टी फेरामोन ट्रेप, प्रकाश प्रपंच आदि तरीकों को अपनाने की सलाह दी।

## सात बातों पर ध्यान दें किसान

- पहली:** एक ही किस्म पर निर्भर रहने की बजाए अलग अलग समयावधि में पकने वाली कम से कम 2-3 किस्मों की खेती करने की साथ ही सोयाबीन प्रजाति जेएस 95-60 में आ रही समस्याओं को देखते हुए विकल्प के रूप में शीघ्र समयावधि में पकने वाली अन्य किस्म जेएस 20-34 की खेती करें।
- दूसरी:** फलियां पकने के समय अधिक समय तक/अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल में हो रहे नुकसान को देखते हुए सोयाबीन किस्मों की विविधता बढ़ाने के लिए जेएस 20-29, जेएस 20-69, जेएस 20-98 जैसी किस्मों का क्षेत्र बढ़ाकर जेएस 95-60 का क्षेत्रफल कम करें।
- तीसरी:** सोयाबीन की बोवनी से पूर्व उपलब्ध अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का अंकुरण परीक्षण कर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकुरण, एवं बीज के आकार के आधार पर 60-80 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग कर बोवनी के समय फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं जैविक कल्चर से बीजोपचार अवश्य करें।
- चौथी:** पीला मोजाइक बीमारी एवं तना मक्खी का प्रकोप को रोकने की लिए फफूंदनाशक से बीजोपचार के पश्चात कीटनाशक थायामिथोक्सम 30 एफएस या इमिडाक्लोप्रिड से बीज उपचार करें।
- पांचवी:** कवकनाशियों द्वारा उपचारित बीज को छाया में सुखाने के बाद जैविक खाद ब्रेडोराइजोबियम कल्चर तथा पीएसबी कल्चर दोनों से टीकाकरण कर तुरंत बोवनी के लिए उपयोग करें।
- छठवीं:** किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्रमानुसार फफूंदनाशक, कीटनाशक से बीजोपचार के बाद ही जैविक कल्चर/खाद द्वारा टीकाकरण करें।
- सातवीं :** कल्चर व कवकनाशियों को एक साथ मिलाकर कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

## अंकुर अभियान के तहत केवीके में हुआ पौधरोपण



**टीकमगढ़।** कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ में अंकुर अभियान के तहत कार्यालय परिसर में उपसंचालक कृषि एसके श्रीवास्तव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, हरीशचंद्र राय, सरपंच माडूमर के हाथों आम की किस्म अमरुद की पौधरोपण, डॉ. बीएस किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा पौधरोपण कराया गया। साथ ही अंकुर अभियान के तहत वायुदूत एप पर भी अपलोड कराया गया। इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान और जयपाल छिगारहा मौजूद थे। कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में अमरुद की चार किस्मों के 30 पौधे और आम की 5 किस्मों के 10 पौधे लगाए जा रहे हैं। जिनमें आगे नई किस्मों के पौधे तैयार कर किसानों को अतिरिक्त आय होगी। साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने और जहरीली गैसों के नियंत्रण का कार्य करेंगे। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि किसानों को वर्चुअल प्रशिक्षण एवं गांव में भ्रमण कर अंकुर अभियान के तहत अधिक से अधिक पौध रोपण के लिए किसानों को प्रेरित व जागरूक करने का कार्य करेंगे। किसानों के खेतों और पोषण वाटिका में पौध रोपण कराकर व्यय और आय में संतुलन बनाएंगे।

## आम और अमरुद से किसानों की बढ़ेगी आय

हंसनाथ खान और जयपाल छिगारहा मौजूद थे। कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में अमरुद की चार किस्मों के 30 पौधे और आम की 5 किस्मों के 10 पौधे लगाए जा रहे हैं। जिनमें आगे नई किस्मों के पौधे तैयार कर किसानों को अतिरिक्त आय होगी। साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने और जहरीली गैसों के नियंत्रण का कार्य करेंगे। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि किसानों को वर्चुअल प्रशिक्षण एवं गांव में भ्रमण कर अंकुर अभियान के तहत अधिक से अधिक पौध रोपण के लिए किसानों को प्रेरित व जागरूक करने का कार्य करेंगे। किसानों के खेतों और पोषण वाटिका में पौध रोपण कराकर व्यय और आय में संतुलन बनाएंगे।

## वैज्ञानिकों ने देखी मूंग की फसल, किसानों दी सलाह

# मंडला में मूंग का पैदावार बढ़ाने में जुटे वैज्ञानिक

संवाददाता, मंडला

कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वैज्ञानिकों डॉ. विशाल मेथ्राम, नीलकमल पंड्रे, डॉ. आरपी अहिरवार, डॉ. प्रणय भारती, केतकी धुमकेती और कान्हा प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ रंजीत कछवाहा द्वारा ग्राम खिरहनी, बिलगांव के मूंग प्रदर्शनों का भ्रमण किया गया। साथ ही किसानों को आवश्यक सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संकुल प्रदर्शन-दलहन एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर (उप्र) के अंतर्गत ग्रीष्म कालीन मूंग का आवंटन किया गया था। जिसे चयनित ग्रामों खिरहनी, बिलगांव, मचला, खुस्सर, डुंगरिया आदि में लॉकडाउन के पूर्व में मूंग की उन्नत किस्म पीडीएम 139 प्रदाय की गई थी। चयनित किसानों को मूंग का उन्नत किस्म पीडीएम 139 का बीज प्रदाय किया गया था जो कि एक उन्नत प्रजाति है जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और ये 60-65 दिनों में ही पककर तैयार हो जाती है। जिससे मानसून आने तक ही कटाई योग्य हो जाने के कारण किसान खरीफकी फसल धान की बोवनी भी समय पर कर सकते हैं।

## पर्याप्त मात्रा में विटामिन

संकुल प्रदर्शन-दलहन एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की आदिवासी उपयोजना का मुख्य उद्देश्य जिले में दलहन के रकबे को बढ़ावा देना है। किसान तैयार उपज को बीज और खाने के लिए गांव में ही विक्रय कर सकते हैं। जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों में प्रोटीन युक्त भोजन की उपलब्धता हो सके। क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट खनिज तत्व व विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

## कतारों में करें मूंग की बोवनी

वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के कारण लॉकडाउन



की स्थिति में केंद्र सरकार और मंडला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों को किसानों को परिपालन करके ही बीजों की बोवनी और समस्त कृषि कार्यों को संपन्न करने की सलाह दी गयी। साथ ही मूंग की वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत पूर्व में ही प्रशिक्षण द्वारा जानकारी दी गई थी कि अच्छी पैदावार के लिए गोबर या कंपोस्ट खाद 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी कतारों में 20 से 25 सेटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए।

## तब रोग मुक्त होगी फसल

गंधक और सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में गंधक युक्त उर्वरक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बोवनी के पहले या बोवनी के समय आधार खाद के रूप में देना चाहिए। खेतों में हर तीसरे वर्ष 6-7 क्विंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। किसान बोवनी से पूर्व राइजोबियम और ट्राइकोडरमा से बीज उपचार

अवश्य करें। जिससे उनकी फसल में उगरा/उकटा रोग न लग पाए।

## इनका कहना है

खरीफ की फसलों जैसे धान, अरहर, आदि की बोवनी के लिए खेत की तैयारी आदान सामग्री जैसे बीज खाद आदि की व्यवस्था करनी है। इसलिए किसान अपने समस्त कार्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन को ध्यान में रखते हुए करें। इससे फसल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी।

**डॉ. विशाल मेथ्राम,** वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, मंडला मूंग एक दाल वाली फसल है जो लेग्यूमिनोसी परिवार में आती है। अतः इसमें नत्रजन (यूरिया) की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए 8-10 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश की मात्रा प्रति एकड़ की दर से बोवनी के समय देना चाहिए।

**डॉ. आरपी अहिरवार,** मृदा वैज्ञानिक, कृषि केंद्र, मंडला

# ज्वार के रकबे को बचाएगी राज विजय-2357 की नई प्रजाति

» ज्वार के अस्तित्व को बचाने जतन में जुटे कृषि वैज्ञानिक  
 » सात साल के लंबे अनुसंधान के बाद तैयार की नई किस्म  
 » स्टेट वेरायटी के रूप में मप्र में उगाने की मिली अनुमति

संवाददाता, इंदौर

किसी समय मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख अनाज की पदवी हासिल करने वाली ज्वार के सिमटते रकबे को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के शासकीय महाविद्यालय की ज्वार सुधार परियोजना के तहत ज्वार की अधिक उत्पादन वाली किस्म राज विजय-2357 (आरवीजे-2357) आई है। नए बीजों को अनुमति देने वाली राज्य स्तरीय समिति ने ज्वार की इस प्रजाति को मंजूरी दे दी है। केवल इसकी अधिसूचना जारी होना बाकी है। सात साल के अनुसंधान के बाद यह किस्म तैयार हुई है, जिसे स्टेट वेरायटी के रूप में मध्यप्रदेश में उगाने की अनुमति मिली है।



## ज्वार की खूबियां

- 43 विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन, प्रोटीन से भरपूर
- ज्वार की नई किस्म आरवीजे-2357 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली किस्मों से इसकी उत्पादकता अधिक है। कृषि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता 35 से लेकर 43 विंटल होगी।
- यह पिछली किस्मों से करीब एक सप्ताह जल्दी पक जाएगी जिसकी अवधि 100-110 दिन होगी। पौधों की ऊंचाई 235 से 150 सेंटीमीटर होगी। बीमारियों के प्रति इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी।
- यह ज्वार मनुष्यों के लिए सुपाच्य प्रोटीन से भरपूर होगी। दानों में प्रोटीन 12.45 प्रतिशत, स्टार्च 61.7 प्रतिशत है। आइरन 20.6 पीपीएम और जिंक 11.8 पीपीएम है।
- अनाज के अलावा पशु आहार के रूप में भी इस कड़बी भी बहुत उत्तम क्वालिटी की होगी जिसका प्रोटीन पशुओं को जल्दी पचेगा।
- करीब 40 साल पहले मध्यप्रदेश में ज्वार का रकबा 25 लाख हेक्टेयर था, लेकिन फिलहाल यह सिमटकर 2.34 लाख हेक्टेयर रह गया है।
- प्रदेश में अब झाबुआ, आलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र से जुड़े क्षेत्रों में ही अब ज्वार उगाई जाती है।

## पांच फिटल ब्रीडर सीड तैयार

ज्वार सुधार परियोजना केंद्र के पास आरवीजे-2357 का करीब पांच फिटल ब्रीडर सीड तैयार हुआ है। यही बीज मध्यप्रदेश के अलग-अलग कृषि विज्ञान केंद्रों को उगाने के लिए दिया गया है, ताकि आने वाले समय में इसका आधार और फिर प्रामाणिक बीज अधिक मात्रा में तैयार किया जा सके। प्रामाणिक बीज तैयार होने के बाद यह आम किसानों को उगाने के लिए मिल सकेगा।

## राज्य स्तर पर मिली मंजूरी

प्रधान वैज्ञानिक और परियोजना के पूवज प्रभारी डा. एके बड़या बताते हैं कि अनुसंधान के दौरान यह बीज भारतीय लघुधान्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद (आइआइएमआर) को भेजा गया था। आईआईएमआर ने इस ज्वार का बीज देश के आठ अलग-अलग ज्वार सुधार परियोजना केंद्रों को उगाकर देखने के लिए दिया था। दो साल तक इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन तीसरे साल यह पीछे रहा। इस कारण यह प्रजाति अखिल भारतीय पर हर राज्य के लिए तो स्वीकार नहीं हो पाई, लेकिन मप्र में राज्य स्तर पर जरूर मंजूरी की गई है।

## इनका कहना है

ज्वार सुधार परियोजना केंद्र के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है कि किसान इसे अपनाएंगे और इससे ज्वार का कम होता रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस ज्वार की कड़बी पशुओं के लिए भी बहुत पाचक आहार होगी।

डॉ. उषा सक्सेना, वैज्ञानिक, केंद्रीय ज्वार प्रजनक

# अब पौधा लगाने पर ही मिलेगी बिल्डिंग परमिशन

विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार का बड़ा फैसला



संवाददाता, भोपाल

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के बिल्डिंग निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। सीएम ने कहा कि हमको अपने लिए अपनों के लिए और इस धरती के लिए पेड़ लगाना चाहिए। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर हम पेड़ लगा सकते हैं। यह उनके जन्मदिन को हमेशा याद दिलाएगा और पर्यावरण को भी स्वच्छ रहेगा। इससे पवित्र कार्य हो ही नहीं सकता। आज

चिंता का विषय है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधन ही नहीं छोड़ें।

## यह होगा नियम

सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। एमपी देश का पहला राज्य होगा जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम से लेकर के नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत स्तर तक ये नियम लागू होगा। यहां किसी भी तरह की इमारत के निर्माण में पौधा लगाना अनिवार्य होगा।

## आम की खास प्रजाति: एमपी के साथ गुजरात के लोगों ने की अग्रिम बुकिंग

# इंदौर में 'शिवराज' के तीन पेड़ में लगे 250 फल, एक हजार में एक 'नूरजहां'

संवाददाता, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर के अपने वजनदार फलों के चलते आमों की मलिका के रूप में मशहूर नूरजहां किस्म के स्वाद के शौकीनों को पिछले साल मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी से इसकी अच्छी फसल हुई है और इसके वजनी आम पकने से पहले ही ऊंचे दामों पर बुक हो चुके हैं। अफगानिस्तानी मूल की मानी जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिने-चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह इलाका गुजरात से सटा है। इंदौर से करीब 250 किमी दूर कट्टीवाड़ा के आम उत्पादक शिवराज सिंह जाधव ने बताया कि मेरे बाग में नूरजहां आम के तीन पेड़ों पर कुल 250 फल लगे हैं। इनकी बुकिंग काफी पहले ही हो चुकी है। लोगों ने नूरजहां के एक आम की 500 से 1000 रुपए के बीच कीमत लगाई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि



नूरजहां आम की अग्रिम बुकिंग करने वाले लोगों में मध्य प्रदेश के साथ ही पड़ोसी गुजरात के शौकीन शामिल हैं। जाधव ने बताया कि इस बार

हुई है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण आमों के कारोबार पर थोड़ा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में नूरजहां के पेड़ों पर संभवतः जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण बौर (आम के फूल) ही नहीं आए थे जिससे शौकीनों को इस आम के खास स्वाद से वंचित रहना पड़ा था।

**जनवरी में आती है बौर:** वर्ष 2019 में नूरजहां के फलों का वजन औसतन 2.75 किलोग्राम के आस-पास रहा था, तब खरीदारों ने इसके केवल एक फल के बदले 1,200 रुपए तक की ऊंची कीमत चुकाई थी। बागवानी के जानकारों ने बताया कि नूरजहां के पेड़ों पर आमतौर पर जनवरी-फरवरी से बौर

नूरजहां आम के फलों का वजन दो से साढ़े तीन किलोग्राम के बीच रहने वाला है।

**एक फीट लंबा फल:** इस बीच, कट्टीवाड़ा में नूरजहां की बागवानी के विशेषज्ञ इशाक मंसूरी ने बताया कि इस बार नूरजहां की फसल तो अच्छी

आने शुरू होते हैं और इसके फल जून की शुरुआत में पककर बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि नूरजहां के भारी-भरकम फल तकरीबन एक फीट तक लम्बे हो सकते हैं और इनकी गुठली का वजन 150 से 200 ग्राम के बीच होता है।

## आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुर्ना से प्रकाशित

# जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

## संपर्क करें

जगत गांव हमार, नमो-1, 1000111111  
 नमो-2, नमो-3, नमो-4, नमो-5, नमो-6, नमो-7, नमो-8, नमो-9, नमो-10, नमो-11, नमो-12, नमो-13, नमो-14, नमो-15, नमो-16, नमो-17, नमो-18, नमो-19, नमो-20, नमो-21, नमो-22, नमो-23, नमो-24, नमो-25, नमो-26, नमो-27, नमो-28, नमो-29, नमो-30, नमो-31, नमो-32, नमो-33, नमो-34, नमो-35, नमो-36, नमो-37, नमो-38, नमो-39, नमो-40, नमो-41, नमो-42, नमो-43, नमो-44, नमो-45, नमो-46, नमो-47, नमो-48, नमो-49, नमो-50, नमो-51, नमो-52, नमो-53, नमो-54, नमो-55, नमो-56, नमो-57, नमो-58, नमो-59, नमो-60, नमो-61, नमो-62, नमो-63, नमो-64, नमो-65, नमो-66, नमो-67, नमो-68, नमो-69, नमो-70, नमो-71, नमो-72, नमो-73, नमो-74, नमो-75, नमो-76, नमो-77, नमो-78, नमो-79, नमो-80, नमो-81, नमो-82, नमो-83, नमो-84, नमो-85, नमो-86, नमो-87, नमो-88, नमो-89, नमो-90, नमो-91, नमो-92, नमो-93, नमो-94, नमो-95, नमो-96, नमो-97, नमो-98, नमो-99, नमो-100, नमो-101, नमो-102, नमो-103, नमो-104, नमो-105, नमो-106, नमो-107, नमो-108, नमो-109, नमो-110, नमो-111, नमो-112, नमो-113, नमो-114, नमो-115, नमो-116, नमो-117, नमो-118, नमो-119, नमो-120, नमो-121, नमो-122, नमो-123, नमो-124, नमो-125, नमो-126, नमो-127, नमो-128, नमो-129, नमो-130, नमो-131, नमो-132, नमो-133, नमो-134, नमो-135, नमो-136, नमो-137, नमो-138, नमो-139, नमो-140, नमो-141, नमो-142, नमो-143, नमो-144, नमो-145, नमो-146, नमो-147, नमो-148, नमो-149, नमो-150, नमो-151, नमो-152, नमो-153, नमो-154, नमो-155, नमो-156, नमो-157, नमो-158, नमो-159, नमो-160, नमो-161, नमो-162, नमो-163, नमो-164, नमो-165, नमो-166, नमो-167, नमो-168, नमो-169, नमो-170, नमो-171, नमो-172, नमो-173, नमो-174, नमो-175, नमो-176, नमो-177, नमो-178, नमो-179, नमो-180, नमो-181, नमो-182, नमो-183, नमो-184, नमो-185, नमो-186, नमो-187, नमो-188, नमो-189, नमो-190, नमो-191, नमो-192, नमो-193, नमो-194, नमो-195, नमो-196, नमो-197, नमो-198, नमो-199, नमो-200, नमो-201, नमो-202, नमो-203, नमो-204, नमो-205, नमो-206, नमो-207, नमो-208, नमो-209, नमो-210, नमो-211, नमो-212, नमो-213, नमो-214, नमो-215, नमो-216, नमो-217, नमो-218, नमो-219, नमो-220, नमो-221, नमो-222, नमो-223, नमो-224, नमो-225, नमो-226, नमो-227, नमो-228, नमो-229, नमो-230, नमो-231, नमो-232, नमो-233, नमो-234, नमो-235, नमो-236, नमो-237, नमो-238, नमो-239, नमो-240, नमो-241, नमो-242, नमो-243, नमो-244, नमो-245, नमो-246, नमो-247, नमो-248, नमो-249, नमो-250, नमो-251, नमो-252, नमो-253, नमो-254, नमो-255, नमो-256, नमो-257, नमो-258, नमो-259, नमो-260, नमो-261, नमो-262, नमो-263, नमो-264, नमो-265, नमो-266, नमो-267, नमो-268, नमो-269, नमो-270, नमो-271, नमो-272, नमो-273, नमो-274, नमो-275, नमो-276, नमो-277, नमो-278, नमो-279, नमो-280, नमो-281, नमो-282, नमो-283, नमो-284, नमो-285, नमो-286, नमो-287, नमो-288, नमो-289, नमो-290, नमो-291, नमो-292, नमो-293, नमो-294, नमो-295, नमो-296, नमो-297, नमो-298, नमो-299, नमो-300, नमो-301, नमो-302, नमो-303, नमो-304, नमो-305, नमो-306, नमो-307, नमो-308, नमो-309, नमो-310, नमो-311, नमो-312, नमो-313, नमो-314, नमो-315, नमो-316, नमो-317, नमो-318, नमो-319, नमो-320, नमो-321, नमो-322, नमो-323, नमो-324, नमो-325, नमो-326, नमो-327, नमो-328, नमो-329, नमो-330, नमो-331, नमो-332, नमो-333, नमो-334, नमो-335, नमो-336, नमो-337, नमो-338, नमो-339, नमो-340, नमो-341, नमो-342, नमो-343, नमो-344, नमो-345, नमो-346, नमो-347, नमो-348, नमो-349, नमो-350, नमो-351, नमो-352, नमो-353, नमो-354, नमो-355, नमो-356, नमो-357, नमो-358, नमो-359, नमो-360, नमो-361, नमो-362, नमो-363, नमो-364, नमो-365, नमो-366, नमो-367, नमो-368, नमो-369, नमो-370, नमो-371, नमो-372, नमो-373, नमो-374, नमो-375, नमो-376, नमो-377, नमो-378, नमो-379, नमो-380, नमो-381, नमो-382, नमो-383, नमो-384, नमो-385, नमो-386, नमो-387, नमो-388, नमो-389, नमो-390, नमो-391, नमो-392, नमो-393, नमो-394, नमो-395, नमो-396, नमो-397, नमो-398, नमो-399, नमो-400, नमो-401, नमो-402, नमो-403, नमो-404, नमो-405, नमो-406, नमो-407, नमो-408, नमो-409, नमो-410, नमो-411, नमो-412, नमो-413, नमो-414, नमो-415, नमो-416, नमो-417, नमो-418, नमो-419, नमो-420, नमो-421, नमो-422, नमो-423, नमो-424, नमो-425, नमो-426, नमो-427, नमो-428, नमो-429, नमो-430, नमो-431, नमो-432, नमो-433, नमो-434, नमो-435, नमो-436, नमो-437, नमो-438, नमो-439, नमो-440, नमो-441, नमो-442, नमो-443, नमो-444, नमो-445, नमो-446, नमो-447, नमो-448, नमो-449, नमो-450, नमो-451, नमो-452, नमो-453, नमो-454, नमो-455, नमो-456, नमो-457, नमो-458, नमो-459, नमो-460, नमो-461, नमो-462, नमो-463, नमो-464, नमो-465, नमो-466, नमो-467, नमो-468, नमो-469, नमो-470, नमो-471, नमो-472, नमो-473, नमो-474, नमो-475, नमो-476, नमो-477, नमो-478, नमो-479, नमो-480, नमो-481, नमो-482, नमो-483, नमो-484, नमो-485, नमो-486, नमो-487, नमो-488, नमो-489, नमो-490, नमो-491, नमो-492, नमो-493, नमो-494, नमो-495, नमो-496, नमो-497, नमो-498, नमो-499, नमो-500, नमो-501, नमो-502, नमो-503, नमो-504, नमो-505, नमो-506, नमो-507, नमो-508, नमो-509, नमो-510, नमो-511, नमो-512, नमो-513, नमो-514, नमो-515, नमो-516, नमो-517, नमो-518, नमो-519, नमो-520, नमो-521, नमो-522, नमो-523, नमो-524, नमो-525, नमो-526, नमो-527, नमो-528, नमो-529, नमो-530, नमो-531, नमो-532, नमो-533, नमो-534, नमो-535, नमो-536, नमो-537, नमो-538, नमो-539, नमो-540, नमो-541, नमो-542, नमो-543, नमो-544, नमो-545, नमो-546, नमो-547, नमो-548, नमो-549, नमो-550, नमो-551, नमो-552, नमो-553, नमो-554, नमो-555, नमो-556, नमो-557, नमो-558, नमो-559, नमो-560, नमो-561, नमो-562, नमो-563, नमो-564, नमो-565, नमो-566, नमो-567, नमो-568, नमो-569, नमो-570, नमो-571, नमो-572, नमो-573, नमो-574, नमो-575, नमो-576, नमो-577, नमो-578, नमो-579, नमो-580, नमो-581, नमो-582, नमो-583, नमो-584, नमो-585, नमो-586, नमो-587, नमो-588, नमो-589, नमो-590, नमो-591, नमो-592, नमो-593, नमो-594, नमो-595, नमो-596, नमो-597, नमो-598, नमो-599, नमो-600, नमो-601, नमो-602, नमो-603, नमो-604, नमो-605, नमो-606, नमो-607, नमो-608, नमो-609, नमो-610, नमो-611, नमो-612, नमो-613, नमो-614, नमो-615, नमो-616, नमो-617, नमो-618, नमो-619, नमो-620, नमो-621, नमो-622, नमो-623, नमो-624, नमो-625, नमो-626, नमो-627, नमो-628, नमो-629, नमो-630, नमो-631, नमो-632, नमो-633, नमो-634, नमो-635, नमो-636, नमो-637, नमो-638, नमो-639, नमो-640, नमो-641, नमो-642, नमो-643, नमो-644, नमो-645, नमो-646, नमो-647, नमो-648, नमो-649, नमो-650, नमो-651, नमो-652, नमो-653, नमो-654, नमो-655, नमो-656, नमो-657, नमो-658, नमो-659, नमो-660, नमो-661, नमो-662, नमो-663, नमो-664, नमो-665, नमो-666, नमो-667, नमो-668, नमो-669, नमो-670, नमो-671, नमो-672, नमो-673, नमो-674, नमो-675, नमो-676, नमो-677, नमो-678, नमो-679, नमो-680, नमो-681, नमो-682, नमो-683, नमो-684, नमो-685, नमो-686, नमो-687, नमो-688, नमो-689, नमो-690, नमो-691, नमो-692, नमो-693, नमो-694, नमो-695, नमो-696, नमो-697, नमो-698, नमो-699, नमो-700, नमो-701, नमो-702, नमो-703, नमो-704, नमो-705, नमो-706, नमो-707, नमो-708, नमो-709, नमो-710, नमो-711, नमो-712, नमो-713, नमो-714, नमो-715, नमो-716, नमो-717, नमो-718, नमो-719, नमो-720, नमो-721, नमो-722, नमो-723, नमो-724, नमो-725, नमो-726, नमो-727, नमो-728, नमो-729, नमो-730, नमो-731, नमो-732, नमो-733, नमो-734, नमो-735, नमो-736, नमो-737, नमो-738, नमो-739, नमो-740, नमो-741, नमो-742, नमो-743, नमो-744, नमो-745, नमो-746, नमो-747, नमो-748, नमो-749, नमो-750, नमो-751, नमो-752, नमो-753, नमो-754, नमो-755, नमो-756, नमो-757, नमो-758, नमो-759, नमो-760, नमो-761, नमो-762, नमो-763, नमो-764, नमो-765, नमो-766, नमो-767, नमो-768, नमो-769, नमो-770, नमो-771, नमो-772, नमो-773, नमो-774, नमो-775, नमो-776, नमो-777, नमो-778, नमो-779, नमो-780, नमो-781, नमो-782, नमो-783, नमो-784, नमो-785, नमो-786, नमो-787, नमो-788, नमो-789, नमो-790, नमो-791, नमो-792, नमो-793, नमो-794, नमो-795, नमो-796, नमो-797, नमो-798, नमो-799, नमो-800, नमो-801, नमो-802, नमो-803, नमो-804, नमो-805, नमो-806, नमो-807, नमो-808, नमो-809, नमो-810, नमो-811, नमो-812, नमो-813, नमो-814, नमो-815, नमो-816, नमो-817, नमो-818, नमो-819, नमो-820, नमो-821, नमो-822, नमो-823, नमो-824, नमो-825, नमो-826, नमो-827, नमो-828, नमो-829, नमो-830, नमो-831, नमो-832, नमो-833, नमो-834, नमो-835, नमो-836, नमो-837, नमो-838, नमो-839, नमो-840, नमो-841, नमो-842, नमो-843, नमो-844, नमो-845, नमो-846, नमो-847, नमो-848, नमो-849, नमो-850, नमो-851, नमो-852, नमो-853, नमो-854, नमो-855, नमो-856, नमो-857, नमो-858, नमो-859, नमो-860, नमो-861, नमो-862, नमो-863, नमो-864, नमो-865, नमो-866, नमो-867, नमो-868, नमो-869, नमो-870, नमो-871, नमो-872, नमो-873, नमो-874, नमो-875, नमो-876, नमो-877, नमो-878, नमो-879, नमो-880, नमो-881, नमो-882, नमो-883, नमो-884, नमो-885, नमो-886, नमो-887, नमो-888, नमो-889, नमो-890, नमो-891, नमो-892, नमो-893, नमो-894, नमो-895, नमो-896, नमो-897, नमो-898, नमो-899, नमो-900, नमो-901, नमो-902, नमो-903, नमो-904, नमो-905, नमो-906, नमो-907, नमो-908, नमो-909, नमो-910, नमो-911, नमो-912, नमो-913, नमो-914, नमो-915, नमो-916, नमो-917, नमो-918, नमो-919, नमो-920, नमो-921, नमो-922, नमो-923, नमो-924, नमो-925, नमो-926, नमो-927, नमो-928, नमो-929, नमो-930, नमो-931, नमो-932, नमो-933, नमो-934, नमो-935, नमो-936, नमो-937, नमो-938, नमो-939, नमो-940, नमो-941, नमो-942, नमो-943, नमो-944, नमो-945, नमो-946, नमो-947, नमो-948, नमो-949, नमो-950, नमो-951, नमो-952, नमो-953, नमो-954, नमो-955, नमो-956, नमो-957, नमो-958, नमो-959, नमो-960, नमो-961, नमो-962, नमो-963, नमो-964, नमो-965, नमो-966, नमो-967, नमो-968, नमो-969, नमो-970, नमो-971, नमो-972, नमो-973, नमो-974, नमो-975, नमो-976, नमो-977, नमो-978, नमो-979, नमो-980, नमो-981, नमो-982, नमो-983, नमो-984, नमो-985, नमो-986, नमो-987, नमो-988, नमो-989, नमो-990, नमो-991, नमो-992, नमो-993, नमो-994, नमो-995, नमो-996, नमो-997, नमो-998, नमो-999, नमो-1000, नमो-1001, नमो-1002, नमो-1003, नमो-1004, नमो-1005, नमो-1006, नमो-1007, नमो-1008, नमो-1009, नमो-1010, नमो-1011, नमो-1012, नमो-101